RNI No.: UPHIN/25/A1697
GARVI GUJARAT
गरवी गुजरात
गरवी गुजरात
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक
वर्ष : 01
अंक : 346
दि. 19.04.2026, रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

राष्ट्र को संबोधन में पीएम ने कहा विपक्षी पार्टियों अपने स्वार्थ के लिए ये बिल पारित नहीं होने दिया

'विपक्ष ने हमारे प्रयास की भ्रूण हत्या की', पीएम मोदी का छलका दर्द

(जीएनएस)।

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल विपल होने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अप्रैल (शनिवार) को रात राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दें पर अपनी बात रखते हुए विपक्ष को जमकर घेरा।

इस संबोधन में महिला आरक्षण बिल के पारित न होने का जिम्मेदार विपक्षी पार्टियों को ठहराते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियों ने अपने स्वार्थ के लिए ये बिल पारित नहीं होने दिया। उन्‍ होंने कहा "बिल गिरा तो मुझे बहुत दुख हुआ। ये सब कुछ देश की नारी शक्ति देख रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने चेतावनी दी कि, "नारी शक्ति अपना अपमान कभी नहीं भूलती है। विपक्ष ने जो पाप किया है उसका उसे सजा मिलेगी।"

"हमारा आत्मबल अजेय है, हमने अभी हार नहीं मानी है"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीस मिनट तक राष्ट्र को संबोधित किया। जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा, "हमारा आत्मबल अजेय है और हमारी सरकार ने अभी हार नहीं मानी है। मेरे लिए देश का हित सबसे ऊपर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए पार्टी का हित ही सब कुछ बन जाता है। जब दलहित, देशहित से बड़ा हो जाता है, तो इसका नुकसान नारी शक्ति और पूरे देश को उठाना पड़ता है-और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला।

"विपक्ष ने हमारे ईमानदारी भरे प्रयास की भ्रूण हत्या कर दी"

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, "मुझे इस बात का खेद है कि विपक्षी पार्टियों ने हमारे ईमानदारी भरे प्रयास की भ्रूण हत्या कर दी है और महिला आरक्षण बिल का विरोध करके देश की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया है और उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया है।"

"मैं इसके लिए सभी माताओं-बहनों से क्षमाप्रार्थी हूं"

पीएम मोदी ने कहा, वे आज खास तौर पर देश की बहनों और बेटियों से संवाद करने आए हैं। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह महिलाओं की प्रगति और उनके सपनों को झटका लगा है। सरकार के पूरे प्रयासों के बावजूद नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित नहीं हो सका। मैं इसके लिए सभी माताओं-बहनों से क्षमाप्रार्थी हूं"

"स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ रहा"

पीएम मोदी ने कहा "कुछ लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि 21वीं सदी की महिलाएं पूरी तरह जागरूक हैं और देश में हो रही हर बात पर उनकी पैनी नजर है। वे न सिर्फ इरादों को समझ रही हैं, बल्कि सच्चाई से भी भली-भांति परिचित हो चुकी हैं। ऐसे में महिला आरक्षण का विरोध करने वाले विपक्षी दलों ने बड़ी गलती की है, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का अपमान किया है। स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है।"

"टीएमसी, डीएमके, कांग्रेस महिला विरोधी"

पीएम मोदी बोले- "कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में पास ना होने पर खुश नजर आ रही थीं। जब महिलाओं के अधिकार प्रभावित हो रहे थे, तब ये दल तालियां बजाकर जश्न मना रहे थे। यह सिर्फ मेज थपथपाना नहीं था, बल्कि नारी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा था।"

लोकसभा में पारित नहीं हुआ महिला आरक्षण बिल

याद रहे संविधान (131वां संशोधन) विधेयक का मुख्य उद्देश्य संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना था। यह विधेयक लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने और 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का परिसीमन करने का भी प्रस्ताव करता था लेकिन निचले सदन में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में सफल नहीं हो सका। सदन में हुए मतदान में 298 सांसदों ने इस बिल के पक्ष में वोट किया, जबकि 230 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। इस परिणाम के बाद से महिला आरक्षण के मुद्दे पर जारी सियासी घमासान और तेज हो गया है।

नोएडा हिंसा का 'मास्टरमाइंड' चढ़ा पुलिस के हत्थे, मजदूरों को उकसाने वाले आदित्य की तमिलनाडु में गिरफ्तारी

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और नोएडा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नोएडा में हुए श्रमिक उपद्रव के मुख्य साजिशकर्ता आदित्य आनंद को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस से बचने के लिए आरोपी अपनी पहचान बदलकर रह रहा था।

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी से बचने के लिए आदित्य आनंद ने अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया था। उसने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली थी और बाल कटवा लिए थे। नोएडा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था।

नोएडा हिंसा का मास्टरमाइंड

पुलिस का मानना है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ भाषण देकर मजदूरों को हिंसा के लिए उकसाने में आदित्य की मुख्य भूमिका थी।

और कौन-कौन थे हिंसा के मुख्य आरोपी?

नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इस पूरे मामले को एक 'दुर्भावनापूर्ण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित गतिविधि' करार दिया है। उन्होंने बताया कि इस हिंसा को भड़काने में मनीषा चौहान, रूपेश राय और आदित्य आनंद के नाम मुख्य रूप से सामने आए हैं।

जांच में क्या क्या खुलासा हुआ?

सुनियोजित साजिशः हिंसा से तीन दिन पहले ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। डिजिटल नेटवर्कः डीसीपी शैव्या गोयल के अनुसार, विरोध प्रदर्शन से पहले 80 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। भटकाने की रणनीतिः इन ग्रुप्स में वेतन वृद्धि या मजदूरों की मांगों पर चर्चा करने के बजाय, फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ और भीड़ जुटाने की योजना साझा की जा रही थी।

होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमला, भारतीय जहाज पर फायरिंग की खबर, ईरान ने बंद किया रास्ता

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बावजूद, र३१३ ङ्ग लङ्ग१४९ को ईरान द्वारा अस्थायी रूप से खोलने की बात कही, फिर दोबारा असमंजस वाली

स्थिति पैदा हुई और आखिर में ईरान ने ट्रंप की अनर्गल बातों के चलते इसे वापस बंद करने का ऐलान कर दिया। इसके ठीक पहले शनिवार को कम से कम आठ तेल और गैस टैंकर इस रास्ते से गुजरे। वहीं, दिन में बाद में, इसी रास्ते से गुजरने वाले दो व्यापारिक जहाजों पर गोलीबारी की खबरें सामने आई।

राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत! दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर पर रोक, कब होगी अगली सुनवाई?

(जीएनएस)।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोपों में ऋक्रदर्ज करने के अपने ही मौखिक आदेश को फिलहाल रोक दिया है। कोर्ट ने माना है कि संभावित आरोपी का पक्ष सुने बिना और उसे नोटिस दिए बिना इस तरह का अंतिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

दरअसल, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने शुक्रवार को खुली अदालत में याचिका पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश सुनाया था। लेकिन इस आदेश के टाइप होने और हस्ताक्षर होने से ठीक पहले, कोर्ट ने 'जगन्नाथ वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' (2014) के एक पुराने फैसले का संज्ञान लिया।

किस आधार पर कोर्ट ने FIR के आदेश पर लगाई रोक

इस फैसले के अनुसार, सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत किसी भी कार्यवाही में जिस व्यक्ति पर आरोप है, उसे अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना अनिवार्य है। इसी कानूनी बिंदु के आधार पर अदालत ने अपने आदेश को रोक दिया।

'BJP का पतन शुरू हो गया', महिला आरक्षण बिल फेल होने पर ममता बनर्जी का दावा, मोदी सरकार के लिए बोली बड़ी बात

'BJP का पतन शुरू हो गया', महिला आरक्षण बिल फेल होने पर ममता बनर्जी का दावा, मोदी सरकार के लिए बोली बड़ी बात

याचिकाकर्ता के गंभीर आरोप और 'ब्रिटिश' नागरिकता का दावा

कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर इस याचिका में कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं:

विदेशी कंपनी का मालिकाना हकः याचिका के अनुसार, राहुल गांधी ने अगस्त 2003 में ब्रिटेन में 'M/S Backops Ltd' नामक एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी।

ब्रिटिश नागरिक के रूप में रजिस्ट्रेशनः दावा किया गया है कि कंपनी के दस्तावेजों में राहुल गांधी ने स्वेच्छा से अपनी राष्ट्रीयता 'ब्रिटिश' बताई थी और उनका पता लंदन और हैम्पशायर का दर्ज है।

एनुअल रिटर्न का विवरणः

याचिका में कहा गया कि अक्टूबर 2005 और 2006 में भरे गए कंपनी के वार्षिक रिटर्न में भी उनकी नागरिकता ब्रिटिश ही दिखाई गई थी, जिसे बाद में 2009 में भंग कर दिया गया

कानूनी उल्लंघनः याचिकाकर्ता का तर्क है कि राहुल गांधी ने 2004 के लोकसभा चुनाव में विदेशी बैंक खातों और कंपनी की जानकारी तो दी, लेकिन नागरिकता छिपाई, जो कि 'आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम' और 'पासपोर्ट अधिनियम' का उल्लंघन है।

कब होगी अगली सुनवाई?

इससे पहले इसी साल जनवरी में लखनऊ की एसीजेएम (ACJM) कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 20 अप्रैल के लिए तय की है।

दिल्ली से यूपी-बिहार के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

गर्मियों की छुट्टियों में घर जाने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी राहत दी है। स्टेशनों पर होने वाली भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए कई समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है।

इस पहल की सबसे खास बात यह है कि इन ट्रेनों को प्रमुख स्टेशनों जैसे आनंद विहार और नई दिल्ली से जोड़ा गया है, जिससे यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने की संभावना काफी बढ़ गई है।

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए आनंद विहार-जोगबनी, नई दिल्ली-सुपौल और अलीपुरद्वार-गोरखपुर जैसे रूटों पर ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमति कुमार ने यह

जानकारी न्यूज-18 को दी। आइए जानते हैं इन ट्रेनों का पूरा शेड्यूल, रूट व टाइमिंग क्या है?

आनंद विहार टर्मिनल-जोगबनी स्पेशल (04008/04007)

कब-कब चलेगीः 11 जुलाई 2026 तक हर शनिवार को (सिर्फ 23 मई को नहीं चलेगी)।

समयः आनंद विहार से सुबह 08:30 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 03:00 बजे जोगबनी पहुंचेगी।

वापसीः हर रविवार शाम 06:30 बजे जोगबनी से चलकर तीसरे दिन सुबह 03:00 बजे दिल्ली आएगी।

इन शहरों से गुजरेगीः गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, गोंडा और गोरखपुर।

कोच की जानकारीः इसमें कुल 19 डिब्बे होंगे, जिसमें एसी, स्लीपर और जनरल क्लास की सुविधा मिलेगी।

2. नई दिल्ली-सुपौल डेली स्पेशल (04072/04071)

कब-कब चलेगीः 15 जुलाई 2026 तक रोज चलेगी (सिर्फ 21 से 25 मई के बीच बंद रहेगी)।

महिला आरक्षण संशोधन बिल क्यों पास नहीं हुआ? आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने बताई वजह, विपक्ष को खूब सुनाया

पवन कल्याण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत की विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने का एक ऐतिहासिक अवसर विपक्ष की ओर से जानबूझकर अवरुद्ध किया गया

(जीएनएस)।

आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने महिला आरक्षण बिल संशोधन पास नहीं होने पर प्रतिक्रिया दी है। पवन कल्याण ने इसके लिए विपक्ष को खूब खरी-खोटी सुनाई है और उन पर राजनीतिक लाभ के लिए महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखने का आरोप भी लगाया है।

मुंबईः साउथ सिनेमा के चर्चित एक्टर, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जन सेना पार्टी की नींव रखने वाले पवन

कल्याण महिला आरक्षण बिल संशोधन पास नहीं होने के कारण काफी निराश हैं। पवन कल्याण ने इसके लिए विपक्ष को खूब खरी-खोटी सुनाई है और उन पर राजनीतिक लाभ के लिए महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखने का आरोप भी लगाया है। इसके साथ पवन कल्याण ने पीएम मोदी की महिला-आधारित नीतियों की खुलकर तारीफ की है और उनका समर्थन भी किया है।

पवन कल्याण ने क्या कहा?

पवन कल्याण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उनके मुताबिक विपक्ष ने जानबूझकर बिल को पास नहीं होने दिया है। पवन कल्याण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत की विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने का एक ऐतिहासिक अवसर विपक्ष की ओर से जानबूझकर अवरुद्ध किया गया है। विपक्ष का यह रुख स्पष्ट करता है कि उनमें भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने और महिलाओं को सशक्त बनाने वाले परिवर्तनकारी सुधारों का समर्थन करने की मंशा नहीं है।

सदन में बिल गिरा तो सड़कों पर फूटा गुस्सा! लखनऊ में 'नारी अधिकारों' के अपमान पर भड़कीं महिलाएं

विश्व हिंदू रक्षा परिषद अपने कार्यलय से महिलाओं के नेतृत्व में पदयात्रा करते हुए कांग्रेस और सपा कार्यालय के बाहर पहुंचीं और जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

(जीएनएस)।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के खिलाफ सदन में विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध किया. इसके चलते बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया. अब विपक्षी दलों के इस रवैये के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर फूटता नजर आ रहा है. लखनऊ के गोमतीनगर में भी विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया. विश्व हिंदू रक्षा परिषद अपने कार्यलय से महिलाओं के नेतृत्व में पदयात्रा करते हुए कांग्रेस और सपा कार्यालय का घेराव करने जा रही थी, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें रास्ते में ही रोक दिया.

प्रदर्शन करने वालीं महिलाओं ने क्या कहा?

प्रदर्शन कर रहीं विश्व हिंदू रक्षा परिषद की महिला कार्यकताओं ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक को सदन में गिराकर कांग्रेस,

सपा और अन्य विपक्षी दलों ने महिलाओं के अधिकारों से उन्हें वंचित करने का प्रयास किया है, जो अत्यंत निंदनीय है.

महिलाओं के अधिकारों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: गोपाल राय

प्रदर्शन में मौजूद अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास न होना केवल एक विधेयक का गिरना नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत सपनों का ठहर जाना है, जो हर उस स्त्री ने देखे हैं जो अपने अस्तित्व को केवल चार दीवारों तक सीमित नहीं रखना चाहती. इस महत्वपूर्ण विधेयक का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना तथा उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है, जो भारतीय संविधान में निहित समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है.

विरोध करने वाले सांसदों के आचरण की संवैधानिक समीक्षा की जाए

ऐसे में कुछ सांसदों द्वारा इस विधेयक के विरोध में मतदान किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक है. यह आचरण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बाधा के रूप में देखा जा सकता है तथा जनभावनाओं के विपरीत भी है. मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मांग करता हूं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वाले सांसदों के आचरण की संवैधानिक एवं नैतिक दृष्टि से समीक्षा कराई जाए तथा उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए.

इतिहास में दर्ज हुआ चिन्नास्वामी स्टेडियम आरसीबी एक विशेष मैदान पर अपने 100 मैच पूरे करने वाली टीम बनी

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम की फिजाओं में आज एक अलग ही उत्साह है। जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की टीम दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैदान पर उतरी, तो उन्होंने क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया। आज का यह मुकाबला केवल एक मैच नहीं, बल्कि आरसीबी के जज्बे और उनके घरेलू मैदान के प्रति वफादारी का एक बड़ा 'सेंचुरी' उत्सव है। आरसीबी

आईपीएल इतिहास की पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने किसी एक विशेष मैदान पर अपने 100 मैच पूरे किए हैं। बेंगलुरु का यह मैदान और आरसीबी की टीम एक-दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। 2008 में इसी मैदान से आईपीएल के सफर की शुरूआत हुई थी, और आज 2026 में आरसीबी ने यहां मैचों का शतक जड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मैदानों के बादशाहः कौन है कहां? RCB: 100 मैच (एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु) KKR: 98 मैच (ईडन गार्डन्स, कोलकाता) कोलकाता नाइट राइडर्स इस सूची में दूसरे नंबर पर है,

सम्पादकीय

मायावती का महिला आरक्षण के विरोधियों पर तीखा प्रहार

महिला आरक्षण को लेकर मायावती का विरोधियों पर तीखा प्रहार मायावती का यह प्रहार सियासी दलों को आईना दिखाता है। वे कहती हैं कि वोट के लिए बहुजन समाज का इस्तेमाल होता है लेकिन हितों की रक्षा नहीं। दलित महिलाएं देश की आधी आबादी का हिस्सा हैं। शिक्षा रोजगार और राजनीति में उनकी भागीदारी कम है। महिला आरक्षण इसे बदल सकता है लेकिन उपकोटा जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि महिला आरक्षण मात्र कानून नहीं बल्कि सियासी हथियार बन गया है। महिला आरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद देश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है।

संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई सीटें आरक्षित करने वाले इस कानून ने सभी दलों को अपनी रणनीति पर पुर्नविचार करने को मजबूर कर दिया है। इसी सिलसिले में बहुजन समाज पाटा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखकर भाजपा कांग्रेस और समाजवादी पाटा पर सीधी चोट की है। उन्होंने कांग्रेस को गिरगिट तक कह डाला है। मायावती का कहना है कि कांग्रेस दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गो के मुद्दों पर दोहरा चरित्र अपनाती रही है।

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों के मामले में कांग्रेस का रिकॉर्ड कभी भरोसेमंद नहीं रहा। मायावती ने आरोप लगाया कि जब वेंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब इन वर्गो को आरक्षण का पूरा लाभ दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस इन वर्गो की बात कर रही है लेकिन यह महज राजनीतिक मजबूरी है।

मायावती ने अपने पोस्ट में भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में रहते हुए दलितों और पिछड़ों के हितों की अनदेखी करती रही है। समाजवादी पाटा को भी उन्होंने पिछड़े वर्गो के प्रति उदासीन बताया। बसपा प्रमुख ने चेतावनी दी कि महिला आरक्षण कानून का लाभ एससी एसटी और ओबीसी महिलाओं को मिलना चाहिए अन्यथा यह कानून मात्र दिखावा साबित होगा। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे इन वर्गो की महिलाओं के लिए वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिाित करें। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है।

इस खबर को गहराई से समझने के लिए हमें पहले महिला आरक्षण अधिनियम के संदर्भ को देखना होगा। यह कानून 128 संशोधन विधेयक के रूप में 2023 में पारित हुआ था। लोकसभा राज्यसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान इसमें है। लेकिन इसका पूर्ण कार्यान्वयन 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद होगा जब परिसीमन होगा। इसी बीच मायावती का यह बयान राजनीतिक दलों के बीच आरक्षण के लाभार्थियों को लेकर हो रही बहस को तेज कर रहा है। बसपा हमेशा से दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर निर्भर रही है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां जातिगत समीकरण निर्णायक होते हैं वहां यह बयान बसपा की रणनीति का हिस्सा लगता है। मायावती का कांग्रेस पर गिरगिट कहना कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद आरक्षण नीतियों को लागू तो किया लेकिन कई बार इसे कमजोर करने की कोशिश भी की। उदाहरण के तौर पर 1990 के मंडल आयोग की सिफारिशों के समय कांग्रेस ने विरोध किया था। वी पी सिह की सरकार ने ओबीसी आरक्षण लागू किया तो कांग्रेस ने इसे अदालत में चुनौती दी। मायावती का इशारा इसी ओर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए एससी एसटी को प्रमोशन में आरक्षण देने से कतरा गई।

2006 में प्रमोशन में आरक्षण बिल लाने की कोशिश हुई लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज जब महिला आरक्षण आया तो कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी महिलाओं के कोटे की बात कर रही है जो पहले कभी नहीं उठाई। यह राजनीतिक उलटपेर मायावती को चुभ रहा है।

नायाब कारीगरी, लखनऊ की इन विरासतों में छिपा है नवाबों का इतिहास

विश्व धरोहर दिवस : बिना खंभों की छत और नायाब कारीगरी, लखनऊ की इन विरासतों में छिपा है नवाबों का इतिहास अगर आप लखनऊ जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह लेख आपके लिए ही है, यहां आपको पर्यटन स्थलों की जानकारी मिल जाएगी.

(जीएनएस)।

लखनऊः अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं और अगली ट्रिप में लखनऊ जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह लेख आपके लिए ही है. इमामबाड़ों की भव्यता से लेकर बेगम हजरत महल पार्क की शानदार सैर तक, यहां आपको पर्यटन स्थलों से लेकर सफर की हर छोटी-बड़ी जानकारी मिल जाएगी, जो आपकी लखनऊ यात्रा के लिए काफी यादगार साबित होगी.

बिना खंभों की छत और नायाब कारीगरी, लखनऊ की इन विरासतों में छिपा है नवाबों का इतिहास

दरअसल, 18 अप्रैल को दुनियाभर में विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है. इसका उद्देश्य मानव सभ्यता से जुड़ी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के प्रति लोगों को जागरूक करना है, ताकि इनके संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित किया जा सके. नवाबों का शहर लखनऊ धरोहरों का खजाना माना

जाता है. यहां की ऐतिहासिक इमारतें देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से आने वाले पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं. बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, हुसैनाबाद घंटाघर, सतखंडा और बारादरी जैसी इमारतें आज भी शहर की ऐतिहासिक पहचान को जीवित रखे हुए हैं. यहां रोजाना हजारों पर्यटक पहुंचकर नवाबी दौर की वास्तुकला, तहजीब और परंपराओं का अनुभव करते हैं. तो चलिए इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि लखनऊ को क्यों देश की सांस्कृतिक राजधानी और विरासतों का गढ़ कहा जाता है, वहां कौन-कौन से पर्यटन स्थल हैं, वहां कैसे पहुंचा जा सकता है?

बड़ा इमामबाड़ा

लखनऊ में कुछ ऐसी इमारतें भी हैं, जो अपनी अनोखी बनावट के कारण आज भी लोगों को चौंका देती हैं. इनमें सबसे खास है बड़ा इमामबाड़ा. इसकी विशाल छत अपनी लंबाई और चौड़ाई के लिए जानी जाती है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस निर्माण में न तो लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और न ही लोहे का. बिना किसी खंभे के खड़ी यह छत इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना मानी जाती है, जो आज भी विशेषज्ञों को हैरान कर देती है. यही अनोखी बनावट देशभर के पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है. लोग यहां पहुंचकर इस ऐतिहासिक धरोहर को करीब से देखते हैं और इसकी बनावट को देखकर अचंभित रह जाते हैं. बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण नवाब आसफ-उद-दौला ने करवाया था. इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी भी जुड़ी हुई है, जो इसे और भी खास बनाती है.

बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण की क्या है दिलचस्प कहानी?

इतिहासकारों के और नवाबी खानदान से मसूद अब्दुल्ला के मुताबिक इस भव्य इमारत का निर्माण वर्ष 1784 में भीषण अकाल के दौरान कराया गया था. इसे अवध के नवाब आसफ-उद-दौला ने बनवाया था, ताकि अकाल से जूझ रहे लोगों को रोजगार मिल सके. इमामबाड़े का मुख्य हॉल अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है. इसकी छत लगभग 50 मीटर लंबी और करीब 16 मीटर चौड़ी मानी जाती है. खास बात यह है कि इतनी बड़ी छत बिना किसी स्तंभ के खड़ी है, जो उस समय की उन्नत निर्माण तकनीक को दशार्ती है.

सीमेंट नहीं, पारंपरिक सामग्री से किया गया था निर्माण

निर्माण में उस दौर की पारंपरिक सामग्री का इस्तेमाल किया गया था. इसमें लखौरी ईंटें, चूना (लाइम प्लास्टर), गुड़, उड़द की दाल और बेल के गूदे का मिश्रण उपयोग में लाया गया था. यह मिश्रण दीवारों और छत को मजबूती देने के साथ-साथ लचीलापन भी प्रदान करता था. विशेषज्ञ बताते हैं कि छत को टिकाए रखने के लिए मेहराब तकनीक का उपयोग किया गया, जिसमें भार को दीवारों में बराबर बांट दिया जाता है. यही वजह है कि बिना खंभों के इतनी विशाल छत सदियों से मजबूती के साथ खड़ी है. आज बड़ा इमामबाड़ा न सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह भारतीय वास्तुकला और इंजीनियरिंग कौशल का जीवंत उदाहरण भी है, जिसे देखने देश-विदेश से पर्यटक लखनऊ पहुंचते हैं.

'मिनी ताजमहल' कहलाने वाला छोटा इमामबाड़ा

नवाबी दौर की शानदार निशानी और 'मिनी ताजमहल' कहलाने वाला छोटा इमामबाड़ा का निर्माण अवध के तीसरे बादशाह नवाब मोहम्मद अली शाह ने वर्ष 1838 में कराया था. यह इमारत दरअसल एक इमामबाड़ा (सभा स्थल) के साथ-साथ उनका मकबरा भी है.

छोटा इमामबाड़ा

क्यों कहा जाता है 'मिनी ताजमहल'?

नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि छोटा इमामबाड़ा को 'मिनी ताजमहल' कहने के पीछे कई खास वजहें हैं. इसकी वास्तुकला में सफेद संगमरमर जैसी चमक और बारीक नक्काशी दिखाई देती है, जो ताजमहल की याद दिलाती है. इमारत के गुंबद, मीनारें के डिजाइन इसे शाही और भव्य रूप देते हैं. अंदर की सजावट में बेल्जियम के झूमर, रंगीन कांच और सुनहरी कलाकारी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी आंतरिक खूबसूरती और भी बढ़ जाती है.

रोशनी और सजावट है मुख्य आकर्षण

छोटा इमामबाड़ा को 'पैलेस ऑफ लाइट्स' भी कहा जाता है. खासकर मुहर्रम के दौरान यहां हजारों दीये और झूमर जलाए जाते हैं, जिससे पूरी इमारत रोशनी में जगमगाती नजर आती है.

पर्यटकों के लिए खास आकर्षण

छोटा इमामबाड़ा न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण बना हुआ है. इसकी भव्यता और नफासत नवाबी दौर की समृद्ध संस्कृति और कला का जीवंत उदाहरण पेश करती है.

लखनऊ में गुमनाम, खास धरोहरें

हुसैनाबाद क्लॉक टॉवर

हुसैनाबाद क्लॉक टॉवर, भारत के सबसे ऊंचे क्लॉक टावरों में से एक है, लेकिन जानकारी न होने की वजह से अक्सर पर्यटक इसे नजरअंदाज कर देते हैं.

दिलकुशा कोठी

दिलकुशा कोठी लखनऊ के शांत कैंटोनमेंट (छावनी) इलाके में गोमती नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक इमारत के अवशेष है. ब्रिटिश दौर की यह इमारत अब खंडहर में बदल चुकी है, लेकिन इसकी वास्तुकला आज भी आकर्षित करती है. यह जगह अपनी वास्तुकला और सुंदर बगीचों के लिए जानी जाती है.

बेगम हजरत महल पार्क

बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ के हृदय स्थल हजरतगंज इलाके में स्थित है. यह पार्क परिवर्तन चौक के पास और होटल क्लार्क अवध के बिल्कुल सामने है. 1857 की क्रांति की वीरांगना की याद में बना यह पार्क इतिहास का अहम गवाह है.

रेजीडेंसी

लखनऊ में रेजीडेंसी शहर के केंद्र में कैसरबाग इलाके में महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित है. यह ऐतिहासिक स्थल हजरतगंज के काफी करीब है और गोमती नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर बना है. 1857 के विद्रोह के निशान आज भी यहां की दीवारों पर देखे जा सकते हैं. यह जगह अपेक्षाकृत कम भीड़ वाली है. ऐसे में अगर आप कम भीड़ और शांति पसंद करते हैं तो यह जगह आपके बेहतर हो सकती है.

कैसे पहुंचे इन धरोहरों तक?

अगर कोई पर्यटक चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचता है, तो इन जगहों तक पहुंचना काफी आसान है.

बेस्ट रूटः चारबाग से हुसैनाबाद क्षेत्र (बड़ा इमामबाड़ा, क्लॉक टॉवर) तक टैक्सी/ऑटो से 20झ30 मिनट.

मेट्रो विकल्पः लखनऊ मेट्रो से ट्रांसपोर्ट नगर से हजरतगंज तक सफर, फिर ऑटो/कैब

लोकल ट्रांसपोर्टः ई-रिक्शा और सिटी बसें आसानी से उपलब्ध

इमामबाड़ा टिकट की कीमत

बड़ा इमामबाड़ाः भारतीय पर्यटकः ₹50, विदेशी पर्यटकः ₹500

छोटा इमामबाड़ाः भारतीय पर्यटकः ₹25झ₹30 (लगभग) विदेशी पर्यटकः ₹300 (लगभग)

नोटः टिकट दरों में समय-समय पर बदलाव संभव है.

हुसैनाबाद ट्रस्ट ने पर्यटकों की सुविधा के लिए डिजिटल मशीन लगाया है, जिससे वह खुद भी इमामबाड़े के अंदर मौजूद मशीन से टिकट निकाल सकते हैं. उसके अलावा बारकोड से भी टिकट ले सकते हैं.

भाषा, खानपान और इमारतों के लिए एक समृद्ध विरासत वाला शहर लखनऊ

लखनऊ। जुबां भी हमारी पहचान है। हम जितने अदब से आदाब बोलते हैं, उतना ही अपनापन "पहले आप" में लुटाते हैं। ये हमारी लखनवी संस्कृति की पहचान ही नहीं विरासत भी है। हमारे शहर की इमारतें, परिधान, कला और संस्कृति भी धरोहर हैं, जो दिन-प्रतिदिन समृद्ध होती जा रही है।

लखनऊ में स्वाद का भंडार है। यहां के खाने जैसा जायका कहीं और नहीं मिलता। यूनेस्को ने गत वर्ष नवंबर में इस शहर को "सिटी आफ गैस्ट्रोनामी" से सम्मानित कर इस बात को स्वीकार किया है। यहां चाट-टिक्की का अलग ही जायका होता है। फिल्म जगत का कोई भी कलाकार हो या फिर अन्य कोई मेहमान, वो लखनऊ आता है तो चाट और अन्य व्यंजनों का स्वाद अवश्य लेता है।

इतिहासकार पद्मश्री डा. योगेश प्रवीन ने अपनी किताब ह्यआपका लखनऊह्न में लिखा है कि दूध और मैदे की बनी बाकरखानी रोटी को यहां के महमूद मियां ने शीरमाल की सूरत दी थी। ईरान और अफगानिस्तान का मशहूर कुलचा भी लखनऊ में आकर अलग स्वाद पा गया।

विश्व धरोहर दिवस वर्ष 1982 में 18 अप्रैल को मनाने की घोषणा की गई थी। वर्ष 1983 में यूनेस्को महासभा ने इसे पूरी तरह से मान्यता दे दी।

हर इमारत की अलग कहानी...

लखनऊ में अनेक इमारते हैं। सबकी अलग कहानी है। यहां की नक्काशी का काम विख्यात है। छतों पर सफेद रंग की नक्काशी संगमरमर सी लगती है, लेकिन वह होती चूने की है। यह शंख और सीप के पाउडर को चूने में मिलाकर बनाई जाती है। बेल बूटों के अलावा चिकनकारी के पैटर्न भी दीवारों पर मिल जाते हैं।

नवाब गाजीउद्दीन हैदर के शासन काल में कोठी दर्शन विलास का निर्माण प्रारंभ कराया गया था। राज्य पुरातत्व निदेशालय के अभिलेखों के अनुसार, 1832 में नवाब नासिरुद्दीन हैदर के समय में यह कोठी बनकर तैयार हुई थी। छतर मंजिल इलाके में बादशाह नासिरुद्दीन हैदर ने प्रियतमा कुदसिया महल के लिए यह महल बनवाया था।

19वीं सदी के चौथे दशक में बादशाह नसीरुद्दीन हैदर ने कोठी गुलिस्ताने इरम का निर्माण कराया था। लाल बारादरी और छोटी छतर मंजिल के मध्य बनवाए गए इस महल का कुछ भाग शेष रह गया है। इस भवन पर यूरोपियन वास्तुकला का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चौक में बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा की विशिष्ट पहचान है तो कैसरबाग में छतर मंजिल भवन इंडो-इटालियन स्थापत्य का बेहतरीन उदाहरण है।

ईरान की गलती से चीन ने ले लिया सबक, एशिया के होर्मुज में छोड़े शिकारी, अमेरिका परेशान पर भारत की भी बढ़ी टेंशन

एक तरफ ईरान में समंदर के अंदर माइंस का खेल चल रहा है, वहीं दूसरी ओर इंडोनेशिया में बाली के पास एक संदिग्ध टॉरपीडो जैसी चीज मिली है. हैरानी की बात ये है कि इसमें चाइनीज डिवाइस लगा हुआ मिला है, जो भारत की भी टेंशन बढ़ाने वाला है जबकि अमेरिका को सीधी चुनौती है.

(जीएनएस)।

इंडोनेशिया के लोम्बोक होर्मुज में एक बड़ा टॉरपीडो जैसा उपकरण मिला है, जिसे रक्षा विशेषज्ञों ने चीनी अंडरवाटर मॉनिटरिंग सिस्टम बताया है. यह खोज चीन की गुप्त जासूसी रणनीति को एक बार फिर बेनकाब कर रही है. पिछले हफ्ते गिली ट्रावांगन द्वीप के उत्तर में एक मछुआरे ने 3.7 मीटर लंबा यह सिलेंडर आकार का उपकरण मछली पकड़ते समय जाल में फंसाया. इंडोनेशियाई नौसेना ने इसे जब्त कर जांच शुरू कर दी. नेवी के प्रवक्ता रियर एडमिरल तुंगुल ने कहा कि हम इसकी उत्पत्ति, उद्देश्य और स्टोर किए गए डेटा की जांच कर रहे हैं.

ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि टॉरपीडो कोई ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि इसमें जो डिवाइस लगाई गई है, वो डीप सी रियल टाइम ट्रांसमिशन मूरिंग सिस्टम है. इसके जरिये समुद्र के अंदर जासूसी की जा सकती है. इसे समुद्री रक्षा विशेषज्ञ एचआई सटन ने इसे चीनी 710 रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाया है. यह उपकरण समुद्र तल पर लंगर डालकर पानी की गहराई, तापमान, लवणता और धाराओं की रीयल-टाइम जानकारी सतह पर भेजता है.

अंडरवॉटर जासूसी क्यों कर रहा है चीन?

चीन की ऐसी डिवाइस का समुद्र की गहराइयों में मिलना कोई संयोग नहीं है, ये रणनीतिक स्ट्रेट में छिपकर घुसपैठ करने और दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाने में मदद करती हैं. हालांकि चीन ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि इसकी ज्यादा व्याख्या की कोई जरूरत नहीं है. दरअसल जब ईरान-अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ था, तो ईरान के कुछ जहाजों को अमेरिकी टॉरपीडो ने डुबो दिया था. ये इस युद्ध में ईरान की बड़ी हार थी, ऐसे में चीन पहले ही ऐसी तैयारी कर चुका है. वो अमेरिकी पनडुब्बियों का पता समुद्र के अंदर ही सेंसर नेटवर्क बिछाकर लगाना चाहता है. लोम्बोक, मलक्का और हार्मुज, ये तीनों जलडमरूमध्य अब सिर्फ व्यापारिक रास्ते नहीं, बल्कि भविष्य के अंडरवाटर युद्ध के मैदान बन चुके हैं, जहां चीन चुपके-चुपके समुद्र के नीचे अपना जाल बिछा रहा है.

पाकिस्तानी बच्चों में तेजी से फैला एचआईवी, अस्पताल की गलती का शिकार बने मासूम, कैसे खुली पोल?

(जीएनएस)।

पाकिस्तान में एक डरावना मामला सामने आया है। जिसमें अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही, असुरक्षित इंजेक्शन और सर्जिकल सामग्री इस्तेमाल करने की वजह से सैंकड़ों बच्चे HIV की चपेट में पाए गए हैं। इस मामले पर रिपोर्टिंग कर रही BBC Eye के मुताबिक, नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच पंजाब प्रांत के तौनसा इलाके में कम से कम 331 बच्चे ल्कक्ष पॉजिटिव पाए गए।

8 साल के बच्चे की मौत ने बढ़ाई चिंता

पीड़ितों में एक 8 साल का बच्चा, मोहम्मद अमीन भी शामिल था, जिसकी बाद में मौत हो गई। कई परिवारों का कहना है कि उनके बच्चों को यह संक्रमण तहसील मुख्यालय (THQ) अस्पताल में इलाज के दौरान लगा। उनका आरोप है कि अस्पताल में इस्तेमाल की गई दूषित सिरिंजों के कारण यह गंभीर स्थिति बनी।

गुप्त फुटेज में दिखी खतरनाक लापरवाही

बीबीसी ने 2025 के अंत में 32 घंटे से ज्यादा का गुप्त वीडियो रिकॉर्ड किया। इस फुटेज में साफ देखा गया कि सिरिंजों को बार-बार मल्टी-डोज शीशियों पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे एक मरीज से दूसरे मरीज तक संक्रमण फैलने का खतरा काफी बढ़ गया। कई मामलों में एक ही शीशी से अलग-अलग बच्चों को दवा दी गई।

सिर्फ सुई बदलना भी नहीं करता सुरक्षित

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अगर सिरिंज का बाकी हिस्सा दूषित है, तो केवल सुई बदलने से भी संक्रमण का खतरा खत्म नहीं होता। जांच में यह भी पाया गया कि अस्पताल में बुनियादी साफ-सफाई के नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा था। कई बार स्टाफ को बिना दस्ताने के इंजेक्शन लगाते और मेडिकल कचरे को गलत तरीके से फेंकते देखा गया।

कार्रवाई के बाद भी नहीं बदले हालात

हालांकि 2024 के अंत में एक निजी क्लिनिक के डॉक्टर ने इस प्रकोप को THQ TÔu»»fsÔ HospitÔl से जोड़ा था, जिसके बाद प्रशासन ने बड़ी

कार्रवाई का वादा किया। मार्च 2025 में अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. तैयब फारूक चंदियो को सस्पेंड भी कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद हालात में कोई बड़ा सुधार नहीं दिखा।

अधिकारियों ने रिपोर्ट पर उठाए सवाल

बीबीसी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कई महीनों बाद भी असुरक्षित प्रथाएं जारी रहीं। हालांकि अस्पताल के अधिकारियों ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि यह फुटेज पुराना या सेटअप किया हुआ हो सकता है और अस्पताल पूरी तरह सुरक्षित है।

नए अधिकारी का दावाः HIV पर फोकस

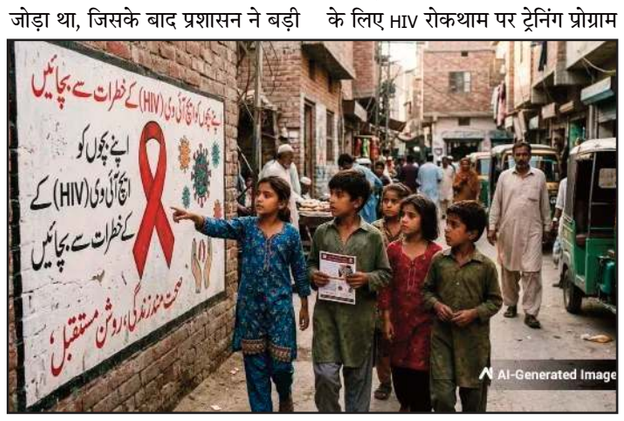

डॉ. चंदियो की जगह बुजदार को नियुक्त किया गया, जिन्होंने मार्च 2025 में पद संभालते ही कहा कि HIV उनका "मुख्य फोकस" है। उन्होंने दावा किया कि अस्पताल में संक्रमण कंट्रोल को लेकर "जीरो टॉलरेंस" नीति अपनाई गई है। बुजदार ने बताया, "हमने पैरामेडिक्स और नर्सों के लिए HIV रोकथाम पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए हैं। सबसे अहम हमारा इंफेक्शन कंट्रोल सेक्शन है, जहां स्टाफ को ठीक से ट्रेन किया गया है।"

ज्यादातर मामलों में दूषित सुई जिम्मेदार

BBC Eye के डेटा एनालिसिस से पता चला कि आधे से ज्यादा मामलों में संक्रमण का कारण दूषित सुइयों को माना गया। सबसे अहम बात यह है कि संक्रमित बच्चों की बहुत कम माताएं ल्कक्ष पॉजिटिव पाई गईं, जिससे यह साफ होता है कि ज्यादातर मामलों में संक्रमण मां से नहीं बल्कि अस्पताल में ही फैला।

पुलकित सम्राट-दिव्येंदु शर्मा के ग्लोरी का ट्रेलर रिलीज, बॉक्सिंग, बदला और मर्डर मिस्ट्री

मून जी

'ग्लोरी' का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई है। पुलकित सम्राट और दिव्येंदु शर्मा स्टारर ये वेब सीरीज महत्वाकांक्षा, बदले और रहस्यमयी हत्या की कहानी को बेहद इंटेंस अंदाज में पेश करती नजर आ रही है। करीब 2 मिनट 27सेकंड के इस ट्रेलर ने दर्शकों के बीच उत्सुकता को कई गुना बढ़ा दिया है।

हरियाणा बॉक्सिंग क्लब से शुरू होती है कहानी

ट्रेलर की शुरूआत हरियाणा के एक बॉक्सिंग क्लब से होती है जिसे चैंपियंस की फैक्ट्री कहा जाता है। कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है जिसने अपने बेटे और भाई को खो दिया है।

उभरते बॉक्सर की रहस्यमयी हत्या पर आधारित है कहानी

सुविंदर विक्की द्वारा निभाया गया रघुबीर सिंह का किरदार एक सख्त लेकिन जुनूनी कोच का है जो अपने सपनों और विरासत को बचाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। वहीं उनकी बेटी गुड़िया जिसका किरदार जन्नत जुबैर ने निभाया है, एक हिंसक हमले का शिकार होती है। इसी बीच एक उभरते बॉक्सर की रहस्यमयी हत्या कहानी को और उलझा देती है।

मजबूत स्टारकास्ट और दमदार किरदारों की टक्कर

वेब सीरीज में आशुतोष राणा का किरदार विजू संघवान कहानी में टकराव को और तेज करता है जबकि सिकंदर खेर शक्तिगढ़ में अपना दबदबा जमाते नजर आते हैं। वहीं सायनी गुप्ता एक जांच अधिकारी के रूप में मर्डर मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश करती दिखती हैं। इनके अलावा यशपाल शर्मा, कश्मीरा परदेशी और कुणाल ठाकुर जैसे कलाकार भी कहानी को मजबूती देते हैं।

'मुन्ना भैया' अवतार में फिर छाए दिव्येंदु शर्मा

ट्रेलर रिलीज के बाद सबसे ज्यादा चर्चा दिव्येंदु शर्मा के किरदार की हो रही है, जिन्हें दर्शक 'मिजार्पुर' के मुन्ना भैया के रूप में पहचानते हैं। उनके इंटेंस लुक और एक्टिंग ने एक बार फिर फैंस का ध्यान खींचा है।

ट्रेलर लॉन्च से पहले पुलकित सम्राट का रियल बॉक्सिंग मुकाबला बना चर्चा का केंद्र

-ट्रेलर रिलीज से पहले पुलकित सम्राट ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। उन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सर नीरज गोयत के साथ लाइव बॉक्सिंग मैच खेला।

-ये सिर्फ प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं थी बल्कि एक असली मुकाबला था, जिसमें पुलकित सम्राट ने पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ हिस्सा लिया था। उन्होंने नीरज गोयत जैसे अनुभवी खिलाड़ी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फाइट की जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

ग्लोबल क्लब में शामिल हुए पुलकित सम्राट

इस मुकाबले के साथ पुलकित सम्राट प्रोफेशनल बॉक्सर के साथ लाइव फाइट करने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं। उन्होंने इस उपलब्धि के साथ खुद को इंटरनेशनल स्टार्स जैसे टॉम हार्डी और जेक गिलेनहाल की लीग में खड़ा कर लिया है, जिन्होंने पहले इस तरह के स्टंट किए हैं।

रियल फाइट ने बढ़ाया वेब सीरीज का क्रेज

इस हाई-एनर्जी मुकाबले ने न सिर्फ दर्शकों को चौंकाया है बल्कि 'ग्लोरी' के एक्शन और इंटेंसिटी की झलक भी पेश की है। बॉक्सिंग रिंग में पुलकित सम्राट का प्रदर्शन ये दिखाता है कि वह अपने किरदार के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं।

क्या 'ग्लोरी' बनेगी अगली बड़ी हिट?

वेब सीरीज के ट्रेलर को मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स और यूनिक प्रमोशन स्ट्रेटजी को देखते हुए 'ग्लोरी' से काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रिलीज के बाद ये सीरीज दर्शकों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

राहुल पर एफआईआर का अपना आदेश हाईकोर्ट जज ने बदला:बिना नोटिस केस दर्ज करना सही नहीं माना; याचिकाकर्ता बोला- सीजेआई से शिकायत करेंगे

लखनऊ , (जीएनएस)।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सांसद राहुल गांधी के खिलाफ ऋक्षक दर्ज करने का अपना ही आदेश बदल दिया है। मामला दोहरी नागरिकता से जुड़ा है। कोर्ट ने शनिवार को अपनी वेबसाइट पर नया आदेश जारी किया।

कोर्ट ने बताया कि शुक्रवार (17 अप्रैल) को सुनवाई हुई थी। इसमें याचिकाकर्ता समेत केंद्र और राज्य सरकार के वकीलों से पूछा गया था कि क्या राहुल गांधी को नोटिस जारी करने की जरूरत है? वकीलों ने नोटिस जारी करने की कोई जरूरत नहीं बताई थी। इसके बाद ऋक्षक दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया था।

हालांकि, आदेश टाइप होने से पहले न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने फिर से फैसले को परखा। उन्होंने पुराने केसों की स्टडी में पाया कि ऐसे मामलों में नोटिस भेजना जरूरी है।

कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को नोटिस जारी किए बिना फैसला करना उचित नहीं है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है।

यह याचिका कर्नाटक में रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने दायर की थी। उन्होंने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता का आरोप लगाते हुए विदेशी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम आदि में केस दर्ज होने की मांग की है।

कोर्ट का फैसला आने के बाद विग्नेश ने कहा- राहुल गांधी के खिलाफ ऋक्षक दर्ज करने का फैसला वापस लेने की शिकायत हम उखक से करेंगे।

कल केस दर्ज करने और उइक से जांच के आदेश दिए थे

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को राहुल गांधी के खिलाफ ऋक्षक दर्ज करने का आदेश दिया था। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा था- ऋक्षक दर्ज करके मामले को उइक को ट्रांसफर किया जाए। हालांकि, इससे पहले 28 जनवरी, 2026 को टढ-टछअ कोर्ट ने विग्नेश शिशिर की याचिका को खारिज कर दिया था।

कोर्ट ने मंत्रालय से ह्यटॉप सीक्रेटह्व फाइलें ली थीं सुनवाई के दौरान जज सुभाष विद्यार्थी ने गृह मंत्रालय के फॉरेनर्स डिवीजन को निर्देश दिए थे कि मामले से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज पेश करें। मंत्रालय ने केस से जुड़ी सभी फाइलें हाईकोर्ट में पेश की थीं।

विग्नेश शिशिर का दावा है कि उन्होंने कोर्ट में दस्तावेज और साक्ष्य पेश किए। इनसे संकेत मिलता है कि राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम में मतदाता रहे हैं। वहां चुनावों में भागीदारी से जुड़े रिकॉर्ड मौजूद हैं।

शुक्रवार को सुनवाई में यूपी सरकार की तरफ से वकील डॉ. बीके सिंह पेश हुए थे। केंद्र सरकार का पक्ष वकील एसबी पांडेय ने रखा। याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर की तरफ से बिंदेश्वरी पांडेय कोर्ट पहुंचे थे।

रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर हुआ था केस

यह शिकायत शुरू में रायबरेली में विशेष टढ/टछअ कोर्ट में दायर की गई थी। हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर, 2025 को इस मामले को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया था।

इसके बाद लखनऊ में टढ/टछअ कोर्ट ने 28 जनवरी, 2026 को याचिका खारिज कर दी। फिर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने पहले ऋक्षक दर्ज करने का आदेश, फिर अपना आदेश पलट दिया।

2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही याचिका खारिज कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में राहुल की भारतीय नागरिकता से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी। उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि अगर कोई कंपनी किसी फॉर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक के तौर मेंशन करती है, तो क्या ऐसा कर देने से ही वे ब्रिटिश नागरिक हो गए।

सीजेआई गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा था- 'हम यह याचिका खारिज करते हैं। इसमें कोई आधार नहीं है। 'याचिका में कहा गया था, 'कोर्ट राहुल की नागरिकता के बारे में मिली शिकायत पर जल्द फैसला करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दे।'

याचिका में राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिए जाने की भी मांग की गई थी। याचिकाकर्ता जय भगवान गोयल ने ब्रिटेन की कंपनी के 2005-06 के सालाना ब्योरे का जिक्र किया था। इसमें कथित तौर पर राहुल को ब्रिटिश नागरिक बताया गया था।

राहुल के खिलाफ यूपी में 3 केस

राहुल के खिलाफ मानहानि का एक केस सुल्तानपुर कोर्ट में चल रहा है। यह मामला 2018 का है। जिसमें बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल पर मानहानि का आरोप लगाया था। 20 फरवरी, 2024 को कोर्ट ने राहुल को 25-25 हजार रुपए के दो मुचलकों पर जमानत दी थी। शुक्रवार, 17 अप्रैल को कोर्ट ने वादी विजय मिश्रा को बार-बार स्थगन आदेश लेने पर कड़ी चेतावनी दी है। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

लखनऊ की एक अदालत में राहुल पर वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान के कारण भी मामला दर्ज है। इस मामले में राहुल गांधी को 200 रुपए का जुमार्ना भी लगाया गया था।

हाथरस की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि केस चल रहा है। बूलगढ़ी गांव के रामकुमार उर्फ रामू ने यह परिवाद दाखिल किया है। आरोप है कि अदालत से दोषमुक्त हुए युवकों को गैंगरेप का आरोपी बताया।

मोदी सरनेम केस में गई थी सांसदी

मोदी सरनेम केस में गुजरात की एक कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त 2023 को उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी।

69000 शिक्षक भर्ती: रउ में सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थी लखनऊ में फिर दिखाएंगे दम, परिजन भी होंगे शामिल

(जीएनएस)।

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 22 अप्रैल को फिर से राजधानी लखनऊ में दम दिखाएंगे। इस बार अभ्यर्थियों के साथ-साथ उनके परिजन भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। वहीं इस मामले में अलग-अलग आंदोलन कर रहे संगठन भी एकजुट होंगे।

अभ्यर्थियों ने बताया कि उनका दो फरवरी से राजधानी के ईको गार्डेन में अनवरत धरना चल रहा है। किंतु सरकार इस मामले में चुप्पी साधे बैठी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार कोई पहल नहीं कर रही। इससे मामला टलता जा रहा है। इस प्रकरण की पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2024 में हुई थी। उसके बाद से लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है।

अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता ने कहा कि पिछली सुनवाई 19 मार्च को होनी थी लेकिन हुई नहीं। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में अनलिस्टेड है। इससे सभी अभ्यर्थियों में बहुत आक्रोश है। हमने 22 अप्रैल को महाआंदोलन करने का फैसला लिया है। सुशील कश्यप ने बताया कि सभी जिले में समन्वयक बनाकर ब्लाक स्तर पर सम्पर्क किया जा रहा है। ताकि अभ्यर्थियों के साथ उनके परिजन भी आ सकें।

आंदोलन में शामिल सुमित कुमार, विक्रम, अमित मौर्या आदि ने कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट और लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला, सब हमारे पक्ष में है। फिर भी हमारे साथ न्याय इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम पिछड़े समाज से आते हैं। सरकार जल्द इस मामले में ठोस पहल नहीं करती है तो आंदोलन व्यापक होगा।

'भाजपा का पतन शुरू हो गया', महिला आरक्षण बिल फेल होने पर ममता बनर्जी का दावा, मोदी सरकार के लिए बोली बड़ी बात

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 18 अप्रैल 2026 (शनिवार) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना केंद्र सरकार पर हमला बोला। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित कराने में विफल केंद सरकार पर ममता बजर्नी ने कहा भाजपा का "पतन" शुरू हो गया है।

'वे दूसरों के सहारे सत्ता में बैठे हैं'

पश्चिम बंगाल में हावड़ा केउलूबेरिया में एक चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने दावा किया, भाजपा "हार चुकी" है और मोदी सरकार केवल सहयोगियों के दम पर सत्ता में है। "भाजपा का पतन शुरू हो गया है। हमने भाजपा को पराजित कर दिया है। उन्हें अपमानित किया गया है। उनके पास अपनी कोई बहुमत नहीं है। वे दूसरों के सहारे सत्ता में बैठे हैं।"

महिला विधेयक आरक्षण बिल हुआ फेल

ममता बनर्जी ने ये टिप्पणी केंद्र के लोकसभा में 2029 से महिलाओं के लिए 33% आरक्षण विधेयक पारित न कर पाने के बाद आई है। याद रहे इसमें 2029 से विधायिकाओं में महिलाओं हेतु 33% आरक्षण और लोकसभा सीटें 816 करने का प्रावधान था। इसके समर्थन में 298 वोट पड़े और 230 वोट इसके खिलाफ गए, लेकिन इसे पारित करने के लिए 352 वोटों की आवश्यकता थी।

'तभी तो बाबू को आज राष्ट्र के नाम संबोधन करना पड़ रहा'

ममता बनर्जी ने कहा, 'कल से पतन शुरू हो गया है, तभी तो बाबू को आज राष्ट्र के नाम संबोधन करना पड़ रहा है।' उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पास अपना बहुमत नहीं है, वह 'दो लोगों के सहारे' बैठी है, और यह सहारा हटने पर सरकार गिर जाएगी।'

ममता बोलीं- भाजपा अब 'धड़ाम धड़ाम' हो रही है

मुख्यमंत्री ममता ने यह भी बताया कि उन्होंने बंगाल चुनाव के दौरान भाजपा को हराने के लिए अपने सांसदों को दिल्ली भेजा था। उन्होंने दावा किया कि 20 से अधिक अन्य पार्टियों के सांसद भी भाजपा के खिलाफ गए। बनर्जी के अनुसार, भाजपा अब 'धड़ाम धड़ाम' हो रही है।

परिसीमन के जरिए भाजपा देश को तोड़ रही

ममता बनर्जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि उन्हें 'बम से भी नहीं डराया जा सकता, गोली से भी नहीं।' उन्होंने दृढ़ता से कहा कि 'जन्म हुआ है तो मौत होगी' पर वह भाजपा से लड़ना नहीं छोड़ेंगी। ममता ने परिसीमन बिल को भाजपा की देश तोड़ने की मंशा का परिणाम बताया।

लोकसभा में पहले से ही 36% महिला सांसद हैं

महिला आरक्षण पर ममता ने अपनी पार्टी टीएमसी का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी में लोकसभा में पहले से ही 36% महिला सांसद और राज्यसभा में 46% महिला सांसद हैं। उन्होंने जोर दिया कि वह 1998 से इस लड़ाई में शामिल हैं और भाजपा को उनसे सीखना चाहिए।

बिस्वा में सरमा बोले- ममता बनर्जी पीएम मोदी से डरती हैं

कूचबिहार में चुनावी दौरे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ममता पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी से डरती हैं क्योंकि वह जानती हैं कि अगर बंगाल में भाजपा आई तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी।

"इखढ पश्चिम बंगाल से ळटउ का कर देगी सफाया"

हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया कि जैसे भाजपा ने गुजरात और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 'हमेशा के लिए बंद कर दिया' है और बिहार में भी ऐसा ही होगा, उसी तरह बंगाल में टीएमसी को भी 'हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा।' उन्होंने विपक्ष के दावों को 'दावे बड़े होते हैं लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता' कहकर खारिज कर दिया।

'राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र...', महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद संजय राउत का बड़ा बयान

महाराष्ट्र से सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश के बहुत प्रभावशाली नेता हैं.

(जीएनएस)।

देश की संसद में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक दो तिहाई बहुमत न होने की वजह से पास नहीं हो पाया. इस बीच राहुल गांधी को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. संसद में बहस के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनौती देते हुए कहा था कि हम इस बिल को यहीं हराएंगे.

वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कल देश के लोकतंत्र बचाने के आंदोलन का नेतृत्व किया है. राहुल गांधी देश के बहुत प्रभावशाली नेता हैं. राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोगों ने कल एक बहुत बड़ी जंग को जीत में बदल दिया है.

मराठी भाषा को लेकर क्या बोले संजय राउत?

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा कि हर राज्य में अपनी मातृभाषा अनिवार्य करनी चाहिए. यह सरकार की नीति है और आरएसएस की भी नीति है कि मातृभाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. इसमें क्या गलत है? महाराष्ट्र की मातृभाषा

मराठी है. वहां काम करने, पढ़ाई करने और आजीविका कमाने वालों को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए.

यह एक राजनीतिक साजिश थी- संजय राउत

सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि महिला आरक्षण विधेयक एक राजनीतिक साजिश थी, और यह विफल हो गई. यह मोदी और उनके गुट के पतन की शुरूआत है. वे महिला आरक्षण की आड़ में मनमाने ढंग से मतदाताओं के गठबंधन में हेरफेर करके सभी चुनाव जीतना चाहते थे. संसद में उनकी ये योजनाएं धराशायी हो गईं. वे लोकसभा सीटों की संख्या मनमाने ढंग से नहीं बढ़ा सके, लेकिन उन्हें संविधान की शक्ति और अपनी वास्तविक ताकत का एहसास हो गया है.

उन्होंने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री का पद केवल 16 सांसदों के बहुमत पर टिका है. अगर ये 16 भी कम हो गए, तो उन्हें अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर बाहर जाना पड़ेगा. आज के घटनाक्रम का यही अर्थ है. मोदी का पतन जल्द ही होने वाला है. मेरी बात याद रखना. राहुल गांधी ने उन 16 सांसदों के गले में फंदा डाल दिया है.

संजय राउत ने बिल को लेकर क्या कहा?

संजय राउत ने बिल पेश होने से पहले कहा था कि महिला आरक्षण के आड़ में जो परिसीमन का खेल चल रहा है, वह बहुत गंभीर है. बीजेपी अपने अनुसार पॉलिटिकल मैप बनाने की कोशिश कर रही है. उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच बीजेपी ने मतभेद पैदा कर दिया है. दक्षिण के राज्यों को कमजोर बना दिया है. दो-चार राज्यों की ताकत इतनी बढ़ा दी है कि वही देश की राजनीति तय करेंगे.

543 सीटों पर क्यों अटका 33% आरक्षण? किसकी गलती, किसका खेल

(जीएनएस)।

लोकसभा में 17 अप्रैल को महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान (131वां संशोधन) बिल पास नहीं हो सका था। इस बिल में लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने और महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव था। बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जबकि इसे पास करने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने (18 अप्रैल) को कैबिनेट मीटिंग में कहा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण का समर्थन न करके गलती की है और उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे।

आखिर इस बिल में ऐसा क्या था जिस पर आम सहमति नहीं बन पाई? क्या यह महिलाओं के हक की लड़ाई

थी या सीटों के गणित का खेल? जिम्मेदार कौन है और आगे क्या होगा। आइए, 10 प्रमुख सवालों (FAQs) के जरिए इस पूरे विवाद को सवाल-जवाब से समझने की कोशिश करते हैं।

संसद में महिला आरक्षण पर महा-मंथनः बड़े सवाल

1. क्या राजनीतिक मतभेद महिलाओं के प्रतिनिधित्व में देरी का असली कारण हैं?

जी हां, भारत में महिला आरक्षण का मुद्दा 1996 से लटका हुआ है। आधिकारिक संसदीय रिकॉर्ड बताते हैं कि हर बार 'कोटा के भीतर कोटा' (ओबीसी आरक्षण) और परिसीमन की शर्तों पर आकर राजनीतिक दल दो धड़ों में बंट जाते हैं। इस बार भी सरकार इसे 'परिसीमन' से जोड़कर लागू करना चाहती थी, जबकि विपक्ष इसे 'बिना शर्त' तुरंत लागू करने की मांग पर अड़ा रहा। यही वैचारिक मतभेद देरी की मुख्य वजह है।

सरकार और विपक्ष दोनों ही महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन तरीका अलग है। सरकार चाहती है कि आरक्षण जनगणना + परिसीमन के बाद लागू हो, जबकि विपक्ष तुरंत लागू करने या डइउ डेटा के साथ लागू करने की मांग कर रहा है।

जबकि 2023 के महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) में साफ लिखा गया था कि नया जनगणना पूरा हो, उसके आधार पर परिसीमन किया जाए, यानी सीधे 543 सीटों पर तुरंत लागू करने का कोई प्रावधान नहीं था। 2023 में पास हुआ बिल में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था Article 334A इसमें लिखा गया है:

आरक्षण तभी लागू होगा जब

कानून लागू होने के बाद पहली जनगणना पूरी हो

और उसके बाद परिसीमन किया जाए

उसी परिसीमन के आधार पर सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी

यह आरक्षण 15 साल तक लागू रहेगा

इसलिए अभी की 543 सीटों पर सीधे लागू करना उस कानून के खिलाफ हो जाता है।

2. बिल अटकने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए?

लोकतंत्र में संसद को चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन संविधान संशोधन जैसे अहम फैसलों के लिए विपक्ष का साथ भी अनिवार्य है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सरकार के पास साधारण बहुमत तो है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए आवश्यक 352 का आंकड़ा (2/3 बहुमत) नहीं था। यहां जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है, सरकार की इस मामले में कि वह सर्वसम्मति बनाने में विफल रही, और विपक्ष की इस मामले में कि उन्होंने संशोधन के मूल ढांचे पर असहमति जताई।

3. क्या विपक्षी दलों को इस सुधार का समर्थन करना चाहिए था?

आदर्श रूप में, महिला सशक्तिकरण जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर आम सहमति होनी चाहिए। हालांकि, विपक्ष का तर्क (जैसा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा) यह है कि वे 'महिला आरक्षण' के विरोधी नहीं हैं, बल्कि उस 'प्रक्रिया' के विरोधी हैं जो जनगणना और सीटों की संख्या बढ़ाने (परिसीमन) से जुड़ी है। विपक्ष का मानना है कि आरक्षण के नाम पर देश का राजनीतिक नक्शा बदलना गलत है।

4. क्या बिल को रोकना सशक्तिकरण के प्रति नकारात्मक संदेश है?

सामाजिक रूप से देखें तो यह निश्चित रूप से एक झटका है। लाखों महिलाएं राजनीति में अपनी हिस्सेदारी का इंतजार कर रही हैं। जब भी कोई ऐसा विधेयक गिरता है, तो जनता के बीच यह संदेश जाता है कि राजनीतिक दल अपने पावर गेम के लिए महिलाओं के अधिकारों को पीछे धकेल रहे हैं। हालांकि, विपक्ष इसे 'संवैधानिक ढांचे को बचाने की लड़ाई' के रूप में पेश कर रहा है।

5. क्या दलों को प्रतिद्वंद्विता से ऊपर उठना चाहिए या विरोध उचित है?

राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर दलों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में 'विरोध' भी एक संवैधानिक अधिकार है। अगर किसी बिल में ऐसे प्रावधान हों जो भविष्य में क्षेत्रीय असंतुलन (उत्तर बनाम दक्षिण भारत) पैदा कर सकते हों, तो उस पर सवाल उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए, विरोध नीतिगत है या राजनीतिक, यह बहस का विषय है।

थलपति जीतेंगे या हारेंगे? क्या डीएमके से छिन जाएगी तमिलनाडु की सत्ता,आया नया सर्वे

(जीएनएस)।

तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों में अभिनेता-राजनेता थलपति विजय के चुनावी रण में उतरने से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक्टर से राजनेता बने थलपति के फैंस उत्सुकता से यह जानने को बेचैन हैं कि क्या वह पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट, इन दो सीटों से जीत हासिल कर पाएंगे। इसके साथ ही लोग जानना चाह रहे हैं कि सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) गठबंधन सत्ता में वापसी होगी या नहीं? जूनियर विकटन के हालिया सर्वे में हैरान करने वाले परिणाम सामने आएं हैं।

थलपति विजय की क्या होगी जीत?

सर्वे के अनुसार विजय जैसे नए राजनीतिक चेहरों का उदय वोटर्स की प्राथमिकताओं को अप्रत्याशित तरीकों से नया आकार दे रहा है। हालिया सर्वे के आंकड़े के अनुसार एक्टर थलपति विजय पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट दोनों सीटों पर शानदार जीत हासिल करेंगे।

क्या DMK से छिन जाएगी की सत्ता?

सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) गठबंधन सत्ता में बने रहने की स्थिति में दिख रही है,जूनियर विकटन का अनुमान है तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में ऊटङ नेतृत्व वाला गठबंधन 121 सीटें हासिल कर बहुमत के आंकड़े (118) को पार करता दिख रहा है। ऊटङ अकेले 97 सीटें जीत सकती है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सीपीआई (मार्क्सवादी) और विदुथलाई चिरुथिगल काची जैसे सहयोगी दलों का भी योगदान रहेगा।

अक्अऊटङ गठबंधन को कितनी मिलेंगी सीटें?

विपक्षी AIADMK गठबंधन को 83 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें अक्अऊटङ 75 सीटें जीत सकती है। बीजेपी और पट्टालि मक्कल काची जैसे छोटे सहयोगी मामूली बढ़त बना सकते हैं, जो करीबी मुकाबले का संकेत है।

तमिलनाडु उट के तौर पर थलपति या स्टालिन कौन है पहली पसंद?

मुख्यमंत्री पद की पसंद के मामले में थलपति विजय ने सबको चौंका दिया है। सर्वे में 44% लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद किया है, जो ऊटङ के एम.के. स्टालिन (28%) और AIADMK के एडप्पाडी के. पलानीस्वामी (25%) से काफी अधिक है। सीमान को 3% लोगों का समर्थन मिला है, जिससे विजय की बढ़ती लोकप्रियता स्पष्ट झलकती है।

किस गठबंधन को कितने फीसदी मिलेगा वोट?

जनता की राय में, ऊटङ गठबंधन को 36%, अक्अऊटङ गठबंधन को 33% और ळशङ को 27% समर्थन मिलने का अनुमान है; नाम तमिलर

काची को 3% वोट मिल सकते हैं। पार्टी-वार वोट शेयर इस प्रकार है- DMK 37.50%, AIADMK 33.63%, TVK 24.71% और नाम तमिलर काची 2.71%।

सवाल यह भी कि क्या अकेले दम पर DMK बना पाएंगी तमिलनाडु में सरकार? सर्वे में यह भी सामने आया है कि खंडित जनादेश की आशंका के बावजूद, अधिकांश उत्तरदाताओं (55.9%) को एकल-पार्टी सरकार की उम्मीद है, जबकि 32.1% गठबंधन सरकार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। केवल 12% लोगों को त्रिशंकु विधानसभा की संभावना दिखती है। हालांकि, 27 ऐसी सीटें हैं जहां मुकाबला बेहद कड़ा है, जो अंतिम परिणामों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।

क्या DMK सरकार से संतुष्ट है तमिलनाडु की जनता? राज्य में सत्ता विरोधी रुझान भी सक्रिय है। 62% उत्तरदाताओं ने सरकार में बदलाव का समर्थन किया है, जबकि 38% लोग मौजूदा सरकार को जारी रखने के पक्ष में हैं। इससे साफ है कि DMK गठबंधन भले ही आगे हो, लेकिन उसे सत्ता विरोधी दबावों का सामना करना पड़ रहा है।

थलपति के चुनाव लड़ने से किसे हो रहा ज्यादा नुकसान?

एक दिलचस्प सर्वे में यह भी पता लगाया कि अगर विजय राजनीति में प्रवेश नहीं करते, तो नाम तमिलर काची को सबसे ज्यादा फायदा होता और उसे 30% से अधिक समर्थन मिलता। AIADMK और DMK को भी कुछ वोट बढ़ते, जिससे यह संकेत मिलता है कि TVK विभिन्न राजनीतिक स्पेक्ट्रम से वोट खींच रही है।

तत्काल चुनावों से परे, भविष्य के राजनीतिक प्रभाव के मामले में भी विजय 47.25% के साथ सबसे आगे हैं। उनके बाद स्टालिन (24.9%) और पलानीस्वामी (15.79%) का स्थान है। के. अन्नामलाई का प्रभाव मात्र 1.28% दर्ज किया गया है।

कुल मिलाकर, DMK गठबंधन को मामूली बढ़त मिली है, लेकिन विजय की TVK का बढ़ता प्रभाव और AIADMK की निरंतर उपस्थिति इस चुनाव को बेहद प्रतिस्पर्धी बनाती है। कई सीटों पर कांटे की टक्कर और बदलाव की मजबूत लहर के बीच, 23 अप्रैल का परिणाम राज्य की राजनीति में अपेक्षित निरंतरता और चौंकाने वाले बदलाव दोनों ला सकता है।

परशुराम जयंती पर छुट्टी पर सियासी संग्राम, सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में योगी सरकार पर निशाना

(जीएनएस)।

लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगे एक पोस्टर ने परशुराम जयंती पर छुट्टी को लेकर सियासी माहौल गरमा दिया है. पोस्टर में योगी सरकार से सवाल उठाए गए हैं. परशुराम जयंती पर छुट्टी पर सियासी संग्राम, सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में योगी सरकार पर निशाना

लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर

राजधानी लखनऊ में एक बार फिर पोस्टर पॉलिटिक्स ने सियासी माहौल गरमा दिया है. समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे एक पोस्टर ने परशुराम जयंती को लेकर

नई बहस छेड़ दी है. इस पोस्टर के जरिए राज्य की राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर खींचतान तेज होती दिख रही है.

सपा कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधा सवाल किया गया है. पोस्टर में लिखा है कि 'परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की शुरूआत सपा सरकार में हुई थी, लेकिन आपने इसे खत्म क्यों कर दिया?' इस लाइन ने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है.

यह पोस्टर मेजर आशीष चतुर्वेदी नाम के शख्स द्वारा लगाया गया है. पोस्टर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है. सपा समर्थक इसे अपनी सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं बीजेपी खेमे में भी इसे लेकर प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं.

लखनऊ : पसमांदा समाज ने किया शक्ति प्रदर्शन, राजनीतिक दलों को लेकर कही बड़ी बात, बताया किसे करेंगे समर्थन

वसीम राइन ने कहा कि पसमांदा मुसलमान लंबे समय से मुख्यधारा से दूर रहे हैं और उन्हें उनका हक नहीं मिला.

लखनऊः (जीएनएस)। राजधानी लखनऊ में पसमांदा समाज का बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जहां प्रदेशभर से आए लोगों ने अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर जोरदार आवाज उठाई. मंच से साफ तौर पर ऐलान किया गया कि जो भी राजनीतिक दल पसमांदा मुस्लिम समाज को उचित प्रतिनिधित्व देगा, समाज उसी के साथ खड़ा होगा.

कार्यक्रम के दौरान ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा संकेत दिया. उन्होंने कहा कि यदि भाजपा पसमांदा समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी देती है तो

समर्थन पर विचार किया जाएगा. साथ ही राज्यसभा और विधान परिषद में भी प्रतिनिधित्व की मांग जोर-शोर से उठाई गई. वसीम राइन ने अपने संबोधन में कहा कि पसमांदा मुसलमान लंबे समय से मुख्यधारा से दूर रहे हैं और उन्हें उनका हक नहीं मिला. उन्होंने कहा कि 'जिस पार्टी से हमें राजनीतिक नेतृत्व और हिस्सेदारी मिलेगी, हम उसी के साथ जाएंगे.'

वसीम राइन ने भाजपा सरकार के कुछ फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि तीन तलाक कानून, आयुष्मान कार्ड, राशन और आवास जैसी योजनाओं से पसमांदा समाज को लाभ मिला है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में पसमांदा समाज के लोगों को विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी दी गई है, जो सकारात्मक संकेत है. वहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इन दलों ने सिर्फ मुस्लिम वोट लिया, लेकिन पसमांदा समाज को न तो नेतृत्व दिया और न ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व. समाजवादी पार्टी के ह्यपीडीएह्ल नारे को उन्होंने छलावा बताया.

लखनऊ में हनी ट्रैप गैंग की सरगना आतिका सिद्दीकी गिरफ्तार, 16 वर्षीय किशोर के परिवार से मांग रही थी रंगदारी

लखनऊ। (जीएनएस)। भोले-भाले युवकों और किशोरों का अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उनके घरवालों से लाखों रुपये वसूलने वाले हनी ट्रैप गिरोह की सरगना आतिका सिद्दीकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आतिका पर लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र के नाबालिग बालक को भगाकर नैनीताल ले जाने का आरोप है।

आरोप है कि नैनीताल में आतिका ने बालक के साथ कई दिन तक जबरिया शारीरिक संबंध बनाया और फिर उसके अश्लील वीडियो बनाकर परिवार के पास भेजकर 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। आतिका ने वीडियो को सोशल मीडिया में भी वायरल करने की धमकी दी थी।

हनी ट्रैप गिरोह की सरगना आतिका सिद्दीकी की धमकियों से परेशान होकर किशोर के घरवालों ने ठाकुरगंज थाना में दुष्कर्म, पाक्सो और रंगदारी का केस दर्ज कराया। वीडियो वायरल करने का दबाव होने के बाद से परेशान परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सख्त कार्रवाई की मांग की थी। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में हनी ट्रैप गिरोह चलाने वाली महिला आतिका को शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

इससे पहले पहले पुलिस ने 16 वर्षीय नाबालिग किशोर का अपहरण कर नैनीताल ले जाकर दुष्कर्म की जांच की और आतिका के खिलाफ दुष्कर्म, पास्को, रंगदारी जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

यह भी पढ़ें- लखनऊ में महिला ने फांसी लगाकर दी जान, पति से हुआ था झगड़ा

आतिका ने भी अपने बचाव में नाबालिग किशोर सहित एक पत्रकार व अन्य दो लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म को आरोप लगाकर थाने में तहरीर दी थी, लेकिन वो पुलिस की जांच में फर्जी साबित हुई। पीड़ित परिवार से 25 लाख की रंगदारी मांगते कई लोगों के कैमरे में कैद होने के बाद पुलिस गंभीर होकर आगे की कार्रवाई में जुटी थी।

लखनऊ में बहन की शादी का कार्ड बांट रहे बड़े भाई की सड़क हादसे में मौत, छोटा भाई और मित्र घायल

(जीएनएस)।

मलिहाबाद (लखनऊ)। माल के शाहपुर गोडवा गांव निवासी युवक अपने भाई और दोस्त के साथ छोटी बहन की शादी का कार्ड बांटने निकला। वापसी के दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। घटना में बड़े भाई की मौके पर ही मौत हो गई। छोटे भाई और एक दोस्त की हालत नाजुक है। पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर-ट्राली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

गोडवा गांव निवासी 26 वर्षीय परमेश्वर की छोटी बहन रेशमा का 24 अप्रैल को तिलक और आगामी 29 अप्रैल को शादी है। पूरा परिवार शादी की तैयारी में लगा था। परेमश्वर चंडीगढ़ में मजदूरी करते थे और बहन की शादी के लिए हाल ही में घर लौटे थे।

शुक्रवार की शाम वह छोटे भाई राम और मित्र रजनेश के साथ बैदानगर निवासी मौसी के घर शादी का कार्ड देकर लौट रहे थे। बहन को दहेज में जो बाइक देनी थी तीनों लोग उसी बाइक से निकले थे। बैदानगर पुलिया के पास तेज रफ्तार अज्ञात ट्रैक्टर-ट्राली ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मारी। टक्कर लगने से तीनों लोग छिटककर सड़क पर गिर गए।

अधिक खून बहने से परमेश्वर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। छोटा भाई और मित्र को गंभीर चोटें आई। घटना के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उनकी हालत स्थिर है। इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर सीसी फुटेज की मदद से ट्रैक्टर-ट्राली का पता लगाया जा रहा है।

सड़क पर बिखरे कार्ड, सदमे में परिवार

घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसे के बाद सड़क पर शादी के कार्ड बिखरे पड़े थे। लोगों को जब पता चला कि बहन की शादी के कार्ड बांट रहे भाई की मौत हुई है तो उन्होंने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कार्रवाई की मांग की। हादसे की सूचना घर पहुंची तो बहन रेशमा बदहवास हो गई। परिवारजन ने किसी तरह उन्हें संभाला। घटना के बाद से शादी की खुशियां गम में बदल गई।

दिल्ली में मौसम खराब होने का वायु सेवा पर बड़ा असर, पुणे जा रही उड़ान वापस लखनऊ लौटी

लखनऊ। (जीएनएस)। दिल्ली में शुक्रवार देर शाम से रात तक मौसम खराब होने का उड़ान सेवा पर बड़ा असर हुआ। वहां पर अचानक मौसम खराब होने के कारण लखनऊ से जाने वाली पांच फ्लाइट को डायवर्ट किया गया।

इंडिगो सहित सभी एयरलाइन ने शुक्रवार देर रात दिल्ली में खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया। इस बीच दिल्ली जा रहीं चार उड़ानों को लखनऊ डाइवर्ट किया गया। इसके साथ ही लखनऊ से पुणे जा रही उड़ान बीच रास्ते से वापस लखनऊ ही लौटी।

हांगकांग से दिल्ली जा रही उड़ान रात 11:38 बजे लखनऊ में उतरी। करीब चार घंटे बाद मौसम सामान्य होने पर उसे सुबह चार बजे दिल्ली रवाना किया गया। वहीं, वडोदरा से दिल्ली जा रही एअर इंडिया की उड़ान एआई-2882 रात 11:30 बजे 138 यात्री और सात क्रू मेंबर के साथ उतरी रात 12:43 बजे दिल्ली रवाना हुई।

मुंबई से दिल्ली जा रही एअर इंडिया की उड़ान एआई-2408 रात 11:39 बजे 164 यात्री और चार क्रू मेंबर के साथ उतरी और रात दो बजे दिल्ली को रवाना हुई। कोलकाता से दिल्ली जा रही अकासा एयर की उड़ान क्यूपी-1804 भी रात 11:45 बजे लखनऊ आई और रात 1:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई। इंडिगो एयरलाइन की उड़ान रात 9:30 पुणे रवाना हुई। वहां रनवे ब्लॉक होने के कारण उड़ान वापस लौट आई।

ऐ साहब ! जर्जर गाड़ियों की ये कैसी फिटनेस ? ताक पर नियम, जेब में फिटनेस !

लखनऊः (जीएनएस)। परिवहन विभाग ने करोड़ों की कीमत से ट्रांसपोर्ट नगर स्थित फिटनेस सेंटर पर आईएनसी खोला था. प्राइवेट हाथों में वाहनों का फिटनेस का काम सौंपने के बाद विभाग ने अपने सरकारी फिटनेस सेंटर में ताला डाल दिया. अब बक्शी का तालाब स्थित ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर पर वाहनों की फिटनेस होती है. हालांकि यहां पर वाहनों की फिटनेस किस तरह से हो रही है वह थोड़ा समझ से परे हैं क्योंकि एटीएस के अंदर से फिटनेस कराने के बाद निकले वाहनों की हालत ठीक नहीं दिखी. वाहनों की लाइट टूटी है, रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप उखड़ा हुआ है, वाहन की हालत कंडम है, लेकिन अंदर से वाहन को फिट होने का प्रमाण पत्र सौंप दिया गया. "ईटीवी भारत" ने जब एटीएस पर वाहनों की फिटनेस का रियलिटी चेक किया उसके बाद अब परिवहन विभाग इस मामले की गंभीरता से जांच कराने की बात कह रहा है.

वाहन चालकों का दावा- पैसा देने पर मिल जाता है फिटनेस सर्टिफिकेट

दरअसल, लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में फिटनेस सेंटर को करोड़ों की लागत से तैयार किया गया. वर्षों तक यहीं पर वाहनों की मशीनों से ही

फिटनेस होती रही. उसके बाद ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन खोलने का प्लान बनाया गया और अब बक्शी का तालाब स्थित एटीएस पर ही वाहनों की फिटनेस हो रही है. 13 अप्रैल को बक्शी का तालाब स्थित ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर जब हमारे सहयोगी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि छत्तीसगढ़ में दर्ज सीजी 10 बीडी 6435 नंबर की गाड़ी आती है. इस गाड़ी की हालत देखकर ही लग जाएगा कि यह सड़क पर चलने काबिल भी नहीं बची है. पता चला कि कुछ दिन पहले इस गाड़ी को मशीनों पर जांचने के बाद फेल दिया गया था. दूसरी बार फिर से स्लॉट लेकर फिटनेस के लिए आने को बोला गया था. देखने में इस गाड़ी में तमाम कमियां नजर आ रही थीं. वाहन के आगे के अस्थि पंजर बिखरे हुए हैं. रिफ्लेक्टिव उजड़ा हुआ है, पिछले हिस्से में कोई टेल लाइट या इंडिकेटर भी नहीं है. हालांकि उसे फिटनेस प्रमाण पत्र दे दिया गया.

फिटनेस प्रमाण पत्र

प्लास्टिक की डोर से रोकी गई नंबर प्लेट, टेप के सहारे हेडलाइट

इसी तरह वढ 32 हठ 0469 इलेक्ट्रिक लोडर फिटनेस के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर पहुंचता है. वाहन पर साफ तौर पर देख रहा था कि किस तरह से हेडलाइट पर टेप चिपका हुआ है, हेडलाइट कहीं अटकी है. इसी तरह नंबर प्लेट भी किसी तरह प्लास्टिक की डोर के सहारे रोकी गई है. वहां बताया गया कि इसमें क्या-क्या कमियां हैं, लेकिन फिर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया. इन वाहनों के चालकों ने कैमरे पर कुछ बोलने से इनकार किया, लेकिन यह बताया कि यहां पर ऐसे लोग सक्रिय हैं जिन्हें पैसा देकर आराम से फिटनेस हो जाता है. दोनों वाहन चालकों ने वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र भी दिखाया कि किस तारीख से लेकर किस तारीख तक के लिए अब गाड़ी पूरी तरह फिट हो गई है.

फिटनेस प्रमाण पत्र आईजीआरएस पर की शिकायत

इसी तरह उन्नाव के सोहरामऊ स्थित ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर अपनी दो साल पुरानी डिजायर गाड़ी वढ 35 इळ 8361 की फिटनेस कराने उन्नाव के वाहन स्वामी आशीष कुमार गए. उन्होंने आरोप लगाया कि मेरी गाड़ी नई है फिर भी फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में ₹5000 मांगे गए. जब मैंने इसका विरोध किया तो कहा गया कि फिटनेस नहीं हो पाएगा. गाड़ी में बताया गया कि प्रदूषण मानक से अधिक उत्सर्जन कर रहा है, जिससे फिटनेस में फेल है. आईजीआरएस पर उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई. आशीष का कहना है कि सबसे गलत बात तो यह है कि जिसकी गाड़ी होती है उसकी आंखों के सामने आखिर मशीनों पर फिटनेस क्यों नहीं होती है, जिससे पता चल सके कि वाकई उसकी गाड़ी में क्या कमी है. एटीएस के अंदर गाड़ी ले जाने पर वहीं के ड्राइवर को गाड़ी सौंपनी पड़ती है, फिर अंदर चाहे वह जो भी करे कौन जानता है. परिवहन विभाग को चाहिए कि वाहन स्वामी को कम से कम अंदर जाने की अनुमति दी जाए, जिससे अपनी आंखों के सामने वाहन की फिटनेस में वाकई कोई दिक्कत है या फिर सिर्फ घूस के लिए फेल की जा रही है, पता तो चल सके.

वहीं, इस मामले में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (लखनऊ जोन) राधेश्याम का कहना है कि ईटीवी भारत ने

लखनऊ में बड़ा हादसा टला, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा से पहले प्रधानाचार्य के कमरे में लगी आग

गोमती नगर के विनय खंड में राजकीय बालिका इंटर कालेज में लगी आग एसी में शार्ट सर्किट के कारण लगी आग पर जल्दी किया गया नियंत्रण

लखनऊ। (जीएनएस)। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रदेश के 217 राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करा रहा है। इसी परीक्षा के दौरान लखनऊ के केंद्र में आग लगने से खलबली मच गई।

लखनऊ में गोमती नगर के राजकीय बालिका इंटर कालेज विनय खंड में शनिवार सुबह आग लग गई। शनिवार को ही कालेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा होनी थी। इस आग लगने की घटना से परिसर में अफरा-तफरी मच गई। आग लगने की सूचना दमकल और पुलिस को दी गई। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।

आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया। छानबीन में पता चला कि आग प्रधानाचार्य के कमरे में लगे एसी में शार्ट सर्किट के कारण लगी थी।गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

यह भी पढ़ें- लखनऊ में विकास नगर कॉलोनी क्षेत्र में आग की चपेट में आने से पांच सौ झोपड़ियां खाक, दो दर्जन सिलिंडर भी फटे

दमकल टीम ने लगभग आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। चपेट में आने कमरे में रखा फर्नीचर और अन्य सामान जल गया है। 1253 पदों पर भर्ती के लिए 1,14,955 आवेदन प्राप्त हुए हैं यानी जिससे प्रति पद औसतन 92 दावेदार हैं।

असिस्टेंट प्रोफेसर (विज्ञापन संख्या-51) की लिखित पुनर्परीक्षा की प्रथम पाली में राजकीय बालिका इंटर कालेज विनयखण्ड-4 गोमती नगर लखनऊ में परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यालय के प्राचार्य कक्ष में एसी के वायरिंग में आग लग गई। परीक्षा केंद्र पर नोडल अधिकारी एवं आयोग से नामित प्रेक्षक योगेन्द्र नाथ सिंह मौजूद थे।

दूसरे कक्ष में हुई परीक्षा

प्रशासन के प्रयास से तत्काल आग पर काबू पाया गया एवं परीक्षार्थियों को अन्य विंग में शिफ्ट करते हुए परीक्षा संपन्न कराई गई।

रूम में चल रहा एसी, ऑपरेशन थिएटर की बत्ती गुल, मरते-मरते बचे मरीज गजब है हाल-ए-पाकिस्तान-

लाहौर (जीएनएस)। पाकिस्तान में बढ़ते बिजली संकट के बीच एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है। दरअसल लाहौर के एक अस्पताल के हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान बिजली चली गई। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था, इसलिए सर्जन इस बात से चिढ़ गए और उन्होंने वीडियो बनाकर मामले को एक्सपोज कर दिया। ऑपरेशन थिएटर में कई मरीजों के ऑपरेशन चल रहे थे जिसकी उनकी जान खतरे में आ गई। वहीं ये मामला अब इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है।

VIP ब्लॉक में लाइट, ऑपरेशन थिएटर में बत्ती गुल

सर्जन के मुताबिक सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अस्पताल के VIP कमरों में जनरेटर से लगातार बिजली मिलती रही, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के जनरेटर का ईंधन खत्म हो गया। यानी जहां मरीजों की जान बचाई जा रही थी, वहां बिजली नहीं थी, लेकिन VIP सुविधा चालू रही।

वीडियो में सर्जन का दर्द और गुस्सा

सर्जन ने एक वीडियो में कहा, "हम सर्विसेज अस्पताल से हैं। यह ऑपरेशन थिएटर है और यहां तीन तरह के मरीजों की सर्जरी चल रही है। इस समय जनरेटर का तेल खत्म हो गया है।" उन्होंने आगे कहा, "VIP ब्लॉक के जनरेटर चल रहे हैं, लेकिन यहां सब बंद है। हमें समझ नहीं आ रहा कि मरीजों को कैसे बचाएं। पिछले 30 मिनट से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं।"

अमीर और गरीब की जान में फर्क

इस घटना ने पाकिस्तान में अमीर और गरीब मरीजों के बीच मौजूद बड़ी असमानता को बाहर ला दिया। वहां

आम लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है। पूरे पाकिस्तान में हालात इतने खराब हैं कि कई इलाकों में 15 घंटे तक की अघोषित बिजली कटौती हो रही है। लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है क्योंकि बिजली कटौती का समय आधिकारिक शेड्यूल से कहीं ज्यादा है।

सरकारी दावे बनाम जमीनी हकीकत

सरकार का कहना है कि पीक टाइम में केवल 2 से 2.5 घंटे की लोड शेडिंग होती है, लेकिन असल में 16 और 17 अप्रैल के बीच शहरी इलाकों में 3 से 8 घंटे या उससे ज्यादा बिजली कटौती हुई। कई जगह यह बिना किसी सूचना के हुई। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति और भी खराब है। यहां 10 से 16 घंटे या उससे ज्यादा समय तक बिजली नहीं रहती। कई जगह तो हर घंटे बिजली जाती रही, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हो गई।

बड़े शहरों में भी लंबी कटौती

Lahore में 3-8 घंटे, Faisalabad में 5-8 घंटे (ग्रामीण इलाकों में ज्यादा), और Multan व दक्षिण पंजाब में 10-16 घंटे तक बिजली कटौती हुई। ये आंकड़े दिखाते हैं कि बड़े शहर भी इस संकट से नहीं बच पाए। Islamabad और Rawalpi»ndi में 4 से 8 घंटे की कटौती दर्ज की गई। वहीं ढीरँ६ं१ और आसपास के इलाकों में 10 से 16 घंटे तक बिजली नहीं रही। इसके अलावा Karachi में K-Electric के तहत आने वाले इलाकों में 2 से 12 घंटे या उससे ज्यादा बिजली कटौती हो रही है। इसके अलावा कसूर, झांग और बलूचिस्तान के कई हिस्से भी बुरी तरह प्रभावित हैं।

2011 जैसे हो रहे हालात

इस गंभीर स्थिति के चलते देशभर में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। कई लोग इसे Pakistan Electricity Crisis 2011 जैसी स्थिति से जोड़कर देख रहे हैं। सर्विसेज अस्पताल की यह घटना सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन यह दिखाती है कि यह बिजली संकट अब सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि जानलेवा बन चुका है। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे, तो इससे और भी बड़े खतरे पैदा हो सकते हैं।